Demand for recognising Kannada as Classical Language

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): This is regarding the demand for recognising 'Kannada' as a 'Classical Language'. A treasure trove of great literary value and antiquity, Kannada meets all the stipulated criteria. Its early texts and recorded history belong to 252 B.C. The first Kannada literary work, 'Kavirajamarga' was created in 850 A.D. and it refers to some writings earlier than that. The 12th Century Kannada Bhakti movement in the form of 'Vachana' or oral expression in unparalleled. Its contemporary 'Keertana', which subsequently become 'Karnataka Sangeetha', is an endearing contribution to Indian music.

Antique Kannada, apart from being literature and culture, also encompassed independent work on many aspects affecting life, *viz.*, medicine, mathematics, veterinary science, agriculture, culinary art and encyclopaedias; in oral and written forms. The epigraphical material in Kannada, numbering over 25,000 inscriptions in stone and copper, are rich in style and content, not found even in Tamil inscriptions. The UNESCO records Kannada as one of the major scripts of the world.

In global perspective, Kannada ranks among the first ten living languages of the world with a history of continuous writing system spanning three millenniums like Hebrew, Chinese and Tamil.

Despite these merits, Kannada is yet to be accorded the 'Classical Language' status. There is simmering discontent and resentment among the people of Karnataka, which is likely to turn violent if the question of recognising Kannada as a 'Classical Language' is not resolved expeditiously. I, therefore, appeal to the Government to decide the issue favourable at the earliest.

Demand to relax the norms for issuance of ARM Licence to PAN Holders

श्री बनवारी लाल कंचाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सदन का ध्यान, जो शस्त्र लाइसेंस दिए जाते हैं, उसमें कानून की जटिलताओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, आज पूरे देश में सरकार को 70 प्रतिशत राजस्व देने एवं 90 प्रतिशत सामाजिक कार्य करने वाले उद्यमियों एवं व्यापारियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस कानूनों में अत्यधिक जटिलता होने के कारण उद्यमियों और व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस देश के विभिन्न स्थानों में नहीं मिल पा रहे हैं। यह दुखद है।

जिस प्रकार से रेल मंत्रालय ने "तत्काल रेल आरक्षण व्यवस्था" लागू करके आम जनता को सुविधा मुहैया कराई है, उसी प्रकार "तत्काल शस्त्र लाइसेंस आवंटन" लागू किया जाए। इस व्यवस्था का लाभ PAN धारक करदाताओं को देते हुए उनसे 1000/- रुपए अतिरिक्त शुल्क लेकर आवेदन की तिथि से एक माह के अंदर शस्त्र लाइसेंस आवंटित किया जाए। इससे उद्यमियों और व्यापारियों में आत्मसुरक्षा का भाव जागृत होगा। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा।

शस्त्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया में इलाके के थानों से रिपोर्ट लगवाने की व्यवस्था की गई है। बहुत से पुलिस अधीक्षक मौखिक निर्देश देकर जिले के संबंधित थानों को रिपोर्ट लगाने के लिए बाध्य करते हैं। तहसीलदार, लेखपाल, दरोगा, सीओ, एसपी, एसएसपी, डीएम आदि अधिकारियों की रिपोर्ट लगवाने में व्यापारी टूट जाता है। अत: सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि PAN धारक करदाताओं के लिए केवल स्थानीय थाना, डीएम एवं एसपी की रिपोर्ट ही पर्याप्त मानी जाये तथा शस्त्र लाइसेंस आवंटन में इसका कड़ाई से पालन कराया जाए। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): सर, मैं एसोसिएट करता हूं।

श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं एसोसिएट करता हूं।

†[شری ابوعاصم اعظمی "اترپردیش" : سر، میں ایسوسی ایٹ کرتا ہوں۔]

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): सर, मैं एसोसिएट करता हूं।

Concern over Horrid Scenario of Crimes against Women

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Sir, according to the National Crime Records Bureau (NCRB), India reports a crime every 17 seconds. In 2005, the country reported 50,26,337 crimes, including 18,22,602 relating to offences under the Indian Penal Code (IPC). The figures could be much higher as only those crimes which were reported to the police were listed. The National Crime Records Bureau Report says that offences against women are most common and are on increase. In